# ब्रिटेन के संदेश की अहमियत

**ब्रिटेन ने फैसला किया है कि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को 80 फीसद तक कम करना है। इसके बाद वह कार्बन उत्सर्जन के मामले में 1990 के स्तर पर आ जाएगा। जलवायु संकट रोकने की दिशा में काम कर रहे सलाहकारों का कहना है कि 2050 तक ग्रीनहाउस गैसों को शून्य तक करना संभव है, लेकिन उसके लिए सार्वजनिक उपभोग, उद्योग और सरकार की नीतियों में बदलाव की जरूरत है।**

**जलवायु** परिवर्तन से निपटने के लिए इमरजेंसी घोषित करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है। इस मुद्दे पर लंदन में ग्यारह दिन तक विरोध चलने के बाद ब्रिटेन की संसद ने पर्यावरण और जलवायु संकट को लेकर इमरजेंसी की घोषणा की है। दिलचस्प यह है कि देश में जलवायु संकट की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष ने इमरजंसी घोषित करने का प्रस्ताव किया और इसे मान लिया गया। यह जान कर आश्चर्य होगा कि इमरजंसी की इस घोषणा से पहले ही देश के दर्जनों शहरों और कस्बों में जलवायु संकट को लेकर आपात स्थिति महसूस की जा रही थी। ब्रिटेन के इस कदम के बाद उम्मीद की जाती है कि दुनिया भर में संसदें और सरकारें जलवायु संकट को धरती का सबसे बड़ा खतरा मानते हुए इस दिशा में गंभीरता से काम करेंगी।

जलवायु संकट एक अपात स्थिति क्यों है, इसे समझने के लिए जानना होगा कि आखिर यह संकट क्या है, क्यों है और इसे कैसे कम किया जाए। असल में भारी औद्योगीकरण और ऊर्जा के साधनों का बेहताशा इस्तेमाल तथा उसमें लगातार वृद्धि इस स्थिति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। इसे नियंत्रण में लाने के लिए सभी देशों में कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की नीतियां तय करनी होंगी और लक्ष्य को 2050 तक हासिल करने के प्रयास करने होंगे। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे आने वाला हर नया वाहन बिजली या सौर ऊर्जा से चलना वाला हो। उसके बाद इन वाहनों को चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। यह बड़ी चुनौती है।

यही नहीं, कृषि आधारित नीतियों को मजबूत करना होगा ताकि अधिक किसानों को प्रोत्साहन मिले। वन्य क्षेत्र में इजाफा करना होगा, 2050 तक जंगलों के दायरे को तेरह से सत्रह फीसद तक बढ़ाना होगा। ब्रिटेन में लोग 2030 तक कार्बन से मुक्ति चाहते हैं, यानी कार्बन उतना ही बने जितना प्राकृतिक रूप से समायोजित किया जा सके। जलवायु परिवर्तन पर आपात स्थिति की मांग एक छोटे-से समूह ने लंदन में की थी। इसके बाद यह आंदोलन बढ़ता हुआ पूरे देश में एक जनांदोलन बन गया। प्रदर्शनकारियों ने शहर की सड़कों को तो बंद किया ही, लंदन की भूमिगत परिवहन प्रणाली को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद ही सरकार ने जलवायु संकट पर इमरजंसी की घोषणा की है।

औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का औसत तापमान साल दर साल बढ़ रहा है। 'इंटर-गवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (आइपीसीसी) की रिपोर्ट ने पहली बार इससे आगाह किया था। अब इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और प्रवृत्ति बढ़ चुकी है। ऐसा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से हो रहा है, जो कारखानों, मशीनों और गाड़ियों से होता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में भी ब्रिटेन गंभीर और अग्रणी दिखाई दे रहा है और यह सिर्फ वहां की सरकार के कारण नहीं है। सच पूछिए तो आम आदमी के कारण इमरजंसी की घोषणा हुई है और जब ऐसा हो गया है तो आगे की कार्रवाई भी होगी। जलवायु के मामले में हम यह सोच कर निश्चिंत नहीं हो सकते कि यह ब्रिटेन की समस्या है।

सच तो यह है कि ब्रिटेन इससे निपटने के उपाय करेगा तो दूसरी जगह इसका असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हर जगह इस पर काम हो और जो स्थिति है, उसमें युद्धस्तर पर काम किए जाने की जरूरत है। भारत में निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने अपने स्तर पर इस दिशा में पहल की है। लेकिन आमतौर पर अभी मामला बहुत ढीला है। सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी बनाया जरूर है और यह प्रदूषण फैलाने वालों को रोकता भी है, पर समस्या विकल्प नहीं होने के कारण ज्यादा गंभीर है। नतीजा यह है कि एनजीटी के फैसले प्रभावी होने के बावजूद परेशान करने वाले होते हैं। इसलिए एनजीटी को लोग मजबूरी मान रहे हैं, जबकि यह जरूरी है और इसके आदेशों-प्रयासों को समझने की जरूरत है।

ब्रिटेन में यह फैसला किया गया है कि वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को अस्सी फीसद तक कम करना है। इसके बाद वह कार्बन उत्सर्जन के मामले में 1990 के स्तर पर आ जाएगा।जलवायु संकट रोकने की दिशा में काम कर रहे सलाहकारों का कहना है कि 2050 तक ग्रीनहाउस गैसों को शून्य तक करना संभव है, लेकिन सार्वजनिक उपभोग, उद्योग और सरकार की नीतियों में बड़े बदलाव की जरूरत है। दूसरी ओर, यह भी तथ्य है कि जो उपाय अभी किए जाएंगे तो उनका प्रभाव 2030 से दिखना शुरू होगा, जबकि 2018 में जलवायु संकट से संबंधित सभी रेकार्ड टूट चुके हैं। ब्रिटेन अठारह विकसित देशों में अकेला है जहां एक दशक में कार्बन उत्सर्जन सबसे कम रहा है। इसकी वजह यह है कि ब्रिटेन 1990 में ही कोयला की जगह प्राकृतिक गैस का उपयोग करने लगा था। 1980-90 में ब्रिटेन के कोयला उद्योग का लगभग सफाया हो गया था। उद्योग के अन्य क्षेत्रों में सन 2000 के अंत में लगभग एक लाख से अधिक नौकरियां चली गई थीं। लेकिन उद्योग के अन्य क्षेत्रों जैसे अक्षय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के निम्न-कार्बन रूपों में अनुसंधान और विकास ने तेजी से प्रगति की है। हाल के दशकों में देखा जा रहा है कि कई विकासशील देश विद्युत ऊर्जा के पक्ष में काम कर रहे हैं, जबकि पहले मना कर चुके थे।

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की तबाही को सीमित करने के लिए हमारे पास सिर्फ बारह साल बचे हैं। ब्रिस्टल कौंसलर कार्ला डेनियर वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार 'क्लाइमेंट चेंज इमरजंसी' घोषित करने का विचार सामने रखा था, जिसे नवंबर में नगर परिषद ने प्रस्ताव के रूप में पास कर दिया। कार्ला डेनियर कहती हैं, 'हमें यह मान लेना चाहिए कि स्थिति गंभीर है। कार्बन उत्सर्जन की कमी के लिए सिर्फ स्थानीय स्तर पर काम करना काफी नहीं है। इसके बारे में सबको जागरूक करने की जरूरत है।' इस बात को जब सबने महसूस किया तो संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौत पर ध्यान केंद्रित किया। पेरिस समझौता 2016 में हुआ था। इसके प्रस्ताव पर एक सौ सनतानवे देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार सभी देश इस बात पर राजी हो गए थे कि वैश्विक तापमान को कम करने के लिए कार्बन का उत्सर्जन भी कम करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य था कि वैश्विक तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना व उद्योगों का तापमान डेढ़ डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होने देना। यह पक्का है कि अगर चाहें तो हम ग्रीनहाउस गैसों के संकट से दूर हो सकते हैं। उसके लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करनी पड़ेगी, जैसा ब्रिटेन ने हाल के वर्षों में किया।

जलवायु संकट एक बड़ी समस्या है और ज्यादातर देशों के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम करना मुश्किल है। हालांकि धीरे-धीरे कुछ देश जागरूक हो रहे हैं। धरती को बचाने के लिए ब्रिटेन जिस रास्ते पर बढ़ा है, बाकी देशों को भी उसी का अनुसरण करना चाहिए।

**मनीषा भट्ट**
**(स्वतंत्र लेखाकार)**

## सम्पादकीय

# मंत्रिपरिषद में नए चेहरे से साफ है कि भाजपा नए और काबिल लोगों को मौके देने वाली पार्टी

मोदी सरकार की वापसी के बाद जिज्ञासा केवल यही नहीं थी कि इस बार किसे मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है, बल्कि यह भी थी कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलता है? इन दोनों सवालों का जवाब सामने आ गया है और सरकार में शामिल हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जहां गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाली वहीं निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय की। अमित शाह ने भाजपा अध्यक्ष के तौर पर जो कुछ हासिल किया वह एक मिसाल है। अब उनसे यही उम्मीद की जाती है कि गृहमंत्री के रूप में भी वह विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए मिसाल कायम करेंगे। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। अब वह वित्त मंत्रालय संभालने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। चूंकि वह आर्थिक मामलों की अच्छी जानकार हैं इसलिए वित्त मंत्री के रूप में उनका चयन उपयुक्त फैसला है। ऐसा ही फैसला विदेश सचिव रहे एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाने का भी है। उनके शपथ लेते ही जहां यह स्पष्ट हो गया था कि वह अगले विदेश मंत्री बनने जा रहे हैं वहीं यह भी कि प्रधानमंत्री विदेश नीति को पहले जैसा ही महत्व देने वाले हैं। राजदूत के तौर पर अमेरिका और चीन में काम कर चुके जयशंकर सुषमा स्वराज की जगह लेंगे जिन्होंने एक छाप छोड़ी है। यह छाप इतनी गहरी है कि विदेश मंत्रालय ही नहीं, देश भी उनकी कमी महसूस करेगा। उन्हें इसके लिए जाना जाएगा कि उन्होंने अपने नेतृत्व में विदेश मंत्रालय को आम आदमी से जोड़ा। मंत्रिपरिषद को सुषमा स्वराज की तरह ही अरुण जेटली की भी कमी महसूस होगी, जिन्होंने सेहत के चलते सरकार से दूर रहने का फैसला लिया। उन्होंने नोटबंदी के साथ ही देश के कर ढांचे की तस्वीर बदलने वाले जीएसटी को ही लागू नहीं कराया, बल्कि हर मुश्किल वक्त पार्टी और सरकार के लिए ढाल भी बने।मंत्रियों के चयन और विभागों के बंटवारे से यह साफ है कि प्रधानमंत्री ने एक ओर जहां नेताओं की क्षमता को महत्व दिया है वहीं निरंतरता का भी ध्यान रखा और शायद इसीलिए आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से भली तरह परिचित राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तरह बेहतर काम कर दिखाने वाले नितिन गडकरी के पास परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तो है ही, उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि वह इन उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। चूंकि उनके कुशल प्रशासक होने में किसी को संदेह नहीं इसलिए एक बार फिर उनसे बेहतर नतीजे देने की उम्मीद की जाती है। ऐसी ही उम्मीद अन्य मंत्रियों से भी की जाती है इसलिए और भी, क्योंकि मोदी सरकार से लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने और नए चेहरों को मंत्री बनाए जाने से मंत्रिपरिषद को जरूरी ऊर्जा और गति मिलनी चाहिए। नए मंत्रियों की क्षमता का आकलन तो उनके कामकाज से ही होगा, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें मंत्रिपरिषद में स्थान देकर यह संदेश भी दिया कि भाजपा नए और काबिल लोगों को मौके देने वाली पार्टी है।

**अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने और नए चेहरों को मंत्री बनाए जाने से मंत्रिपरिषद को जरूरी ऊर्जा और गति मिलनी चाहिए।**